Original Article
ISSN(Online): 3139-4434
https://ijeagr.com/

International Journal of Educational Analysis and Global Research
International Open Access, Peer-Reviewed, Refereed Journal
Volume 01, Issue 02, May 2026

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और उसका सामाजिक प्रभाव चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

लईक अहमद[1], डॉ. जयसिंह राठौर[2]

[1]शोध छात्र, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छत्तरपुर, मध्यप्रदेश।

[2]एसोसिएट प्रोफेसर, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छत्तरपुर, मध्यप्रदेश।

Email: laique15686@gmail.com

Received 05 May 2026

Accepted 15 May 2026

Published 20 May 2026

Corresponding Author:
लईक अहमद

Email: laique15686@gmail.com

Doi: https://doi.org/10.64880/ijeagr.v1i2.07

Funding: This research received no specifics grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sector.

Copyright: © 2026 The Author(s). This is an open access article under the Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License.

OPEN ACCESS

सारांश

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसने वैश्विक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत ढांचों को प्रभावित किया है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान कर रहा है, जिसका असर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, न्याय प्रणाली, प्रशासन और श्रम बाजार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। इस सन्दर्भ में, AI न केवल कार्यकुशलता और उत्पादकता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि इससे सामाजिक सम्बन्धों और मानव व्यवहार के स्वरूप को भी पुनर्परिभाषित किया है। इस शोध का उद्देश्य भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास की प्रवृत्तियों और उसके सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन विशेष रूप से रोजगार संरचना में बदलाव, सामाजिक असमानता, डिजिटल विभाजन, डेटा गोपनीयता और नैतिक जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। शोध यह स्पष्ट करता है कि जहाँ AI तकनीकी सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार कर सकती है, इसके अनियंत्रित और असमान उपयोग से सामाजिक विषमता और मानव अधिकारों से जुड़े नए चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है जिसमें सरकारी नीतिगत दस्तावेजों, नीति आयोग की रिपोर्टों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशनों और समकालीन शोध लेखों का विश्लेषण किया गया है। शोध निष्कर्षतः यह दर्शाता है कि भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास एक समावेशी, नैतिक और मानव केंद्रित नीति ढांचे के तहत होना आवश्यक है ताकि तकनीकी प्रगति सामाजिक न्याय और सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप हो सके।

मुख्य शब्द *- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक प्रभाव, डिजिटल परिवर्तन, रोजगार संरचना, डेटा गोपनीयता, नैतिक शासन।*

प्रस्तावना

वर्तमान युग को तकनीकी नवाचारों का युग माना जा सकता है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत जैसे विकासशील और सामाजिक रूप से विविध देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन की दिशा और स्वरूप को भी प्रभावित कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में AI आधारित प्रणालियों का बढ़ता उपयोग भारतीय समाज में नए संस्थागत बदलावों के द्वार खोल रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मुख्य उद्देश्य मानव बुद्धि की क्षमताओं, जैसे- सीखना, विश्लेषण करना और निर्णय लेने को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। भारत सरकार ने 'डिजिटल इंडिया', 'स्टार्ट-अप इंडिया' और ''AI FOR ALL'' जैसी पहलों के माध्यम से AI को राष्ट्रीय विकास की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। इसके परिणामस्वरूप सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और पहुँच में सुधार हुआ है, जिससे आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं।

यद्यपि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार के साथ कई सामाजिक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। रोजगार संरचना में बदलाव, मानव श्रम का प्रतिस्थापन, डेटा गोपनीयता, निगरानी संस्कृति और नैतिक जिम्मेदारी जैसे मुद्दे भारतीय समाज के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन गए हैं। डिजिटल विभाजन और सामाजिक असमानता की मौजूदा स्थिति में, AI का असंतुलित विकास समाज के कमजोर वर्गों को और अधिक हाशिए पर धकेल सकता है।

इस पृष्ठभूमि में यह आवश्यक हो जाता है कि भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उसके सामाजिक प्रभावों का समग्र अध्ययन किया जाए। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य AI से जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों का संतुलित विश्लेषण करना है ताकि यह समझा जा सके कि तकनीकी प्रगति को किस प्रकार मानव-केंद्रित, नैतिक और समावेशी दृष्टिकोण के साथ अपनाया जा सकता है।

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास

इक्कीसवीं सदी में तकनीकी परिवर्तन ने वैश्विक समाज को एक नई दिशा दी है और इस परिवर्तन के केन्द्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी है। भारत जैसे विकासशील देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचों में व्यापक बदलाव का संकेत भी करता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की मजबूत स्थिति ने AI के विकास के लिए एक अनुकूल आधार तैयार किया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तात्पर्य उन प्रणालियों से है, जो मानव बुद्धि की तरह सीखने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। भारत में AI का प्रारम्भिक उपयोग मुख्यतः आईटी सेवाओं और स्वचालन तक सीमित था, लेकिन अब इसका विस्तार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, रक्षा और प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। उदाहरण के तौर पर, स्वास्थ्य क्षेत्र में रोग निदान, कृषि में फसल पूर्वानुमान और प्रशासन में ई-गवर्नेंस के माध्यम से AI आधारित तकनीकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

भारत सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत ''AI FOR ALL'' की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि AI को केवल आर्थिक लाभ का साधन नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। 'डिजिटल इंडिया' और 'स्टार्ट-अप इंडिया' जैसी पहलों ने नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करके AI आधारित स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में मदद की है। जिसके परिणामस्वरूप भारत में AI अनुसंधान, कौशल विकास और उद्यमिता के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं।

हालांकि, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास से जुड़ी कई चुनौतियाँ भी हैं। डेटा गुणवत्ता, डिजिटल अवसंरचना की असमान उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन की कमी और नैतिक व कानूनी ढांचे का अभाव प्रमुख समस्याएँ हैं। साथ ही, स्वचालन के कारण रोजगार में संभावित परिवर्तन सामाजिक असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास की संभावनाएँ बहुत बड़ी हैं। यदि AI का विकास मानव-केंद्रित, समावेशी और नैतिक दृष्टिकोण से किया जाए, तो यह सामाजिक विकास, प्रशासनिक पारदर्शिता और आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी साधन बन सकता है। इस तरह भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास न केवल तकनीकी शक्ति को उभार देगा, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा भी निर्धारित करेगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सामाजिक प्रभाव : कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने समाज के कार्य करने के तरीकों को तेजी से बदला है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुविधाएँ बढ़ी हैं, पर साथ ही गोपनीयता, समानता और मानवीय मूल्यों से जुड़ी नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। मानव-केंद्रित उपयोग से ही इसका सामाजिक लाभ सुनिश्चित हो सकता है।

शिक्षा पर प्रभाव

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में सीखने और सिखाने की पारंपरिक प्रक्रियाओं को नई दिशा दी है। भारत में AI आधारित तकनीकों का उपयोग शिक्षा को और अधिक सुलभ, व्यक्तिगत और प्रभावी बनाने में सहायक साबित हो रहा है। स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल ट्यूटर और अनुकूलनी शिक्षण प्रणाली विद्यार्थियों की सीखने की गति और रुचियों के अनुसार सामग्री प्रस्तुत करती है, जिससे सीखने की गुणवत्ता में सुधार होता है।

शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव मूल्यांकन और प्रशासनिक कार्यों पर देखा जा सकता है। स्वचालित मूल्यांकन प्रणाली शिक्षकों का कार्यभार कम करती है और विद्यार्थियों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करती है। इसके अलावा, AI आधारित विश्लेषण से कमजोर छात्रों की पहचान कर उन्हें समय पर सहायता प्रदान की जा सकती है, जिससे ड्राप आउट दर में कमी लाई जा सकती है।

यद्यपि, शिक्षा में AI के प्रयोग से कुछ सामाजिक चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। डिजिटल अवसंरचना की असमान उपलब्धता के कारण ग्रामीण और वंचित वर्ग के विद्यार्थी AI आधारित शिक्षा से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पाते। साथ ही, अत्यधिक तकनीकी निर्भरता से शिक्षक-विद्यार्थी संबंधों में दूरी आने की आशंका भी व्यक्त की जाती है।

इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मानव-केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण के साथ किया जाए। यदि AI को शिक्षक के सहयोगी के रूप में विकसित किया जाए, न कि उसके विकल्प के तौर पर, तो यह शिक्षा प्रणाली को अधिक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और प्रभावी बना सकता है।

रोजगार पर प्रभाव

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने रोजगार की प्रकृति और संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव लाना शुरू कर दिया है। भारत में AI आधारित स्वचालन ने कई क्षेत्रों में कार्यकुशलता बढ़ाई है, विशेष रूप से उद्योग, बैंकिंग, आईटी और सेवा क्षेत्र में। इससे समय और लागत की बचत हुई है, लेकिन इस प्रक्रिया ने पारंपरिक और नियमित कामों में लगे श्रमिकों के लिए रोजगार की असुरक्षा भी पैदा की है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण कुछ नौकरियों के खत्म होने का खतरा है, लेकिन इसके साथ-साथ नए प्रकार के रोजगार के अवसर भी सामने आ रहे हैं, जैसे - डेटा विश्लेषण, AI विकास, साइबर सुरक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण। यह बदलाव इस बात का संकेत देता है कि रोजगार का स्वरूप समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि बदल रहा है।

हालांकि, भारत जैसे देश में कौशल असमानता और डिजिटल विभाजन के कारण सभी वर्ग इन नए अवसरों का समान लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि AI के साथ कौशल विकास और पुनः प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के लिए चुनौती नहीं बल्कि अवसर बन सके।

सामाजिक संबंधों पर प्रभाव

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मानव समाज के आपसी संबंधों को नए तरीके से आकार देना शुरू कर दिया है। डिजिटल सहायक, सोशल मीडिया, एल्गोरिदम और आभासी संवाद प्रणालियों ने लोगों के संवाद के तरीकों को और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। परिवार, दोस्ती और कार्यस्थल जैसे सामाजिक वातावरण में AI आधारित तकनीकों ने समय और दूरी की बाधाओं को कम किया है, जिससे संपर्क अधिक सहज हो गया है।

यद्यपि, सामाजिक संबंधों पर AI का प्रभाव केवल सकारात्मक नहीं है। आभासी संवाद की बढ़ती प्रवृत्ति ने सीधा मानवीय संपर्क कम कर दिया है, जिससे भावनात्मक दूरी और अकेलेपन की भावना बढ़ने का खतरा पैदा होता है। सोशल मीडिया में इस्तेमाल किए जाने वाले एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं की पसंद के अनुसार सामग्री पेश करते हैं, जिससे विचारों का दायरा संकुचित हो सकता है और सामाजिक विभाजन की स्थिति बन सकती है।

इसके अलावा, निर्णय-निर्माण में AI के बढ़ते उपयोग से विश्वास और उत्तरदायित्व जैसे मानवीय मूल्यों पर भी सवाल उठते हैं। जब मशीनें मानवीय व्यवहार का विश्लेषण करने लगती हैं, तब गोपनीयता और स्वायत्तता से जुड़ी चिंताएं सामने आती हैं।

इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक संबंधों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण से किया जाए। यदि AI को मानवीय संवेदनाओं के पूरक के रूप में अपनाया जाए, न कि उनके विकल्प के रूप में, तो यह सामाजिक संबंधों को सशक्त और अधिक अर्थपूर्ण बना सकती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास की चुनौतियाँ

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न चुनौतियाँ बहुआयामी हैं। इन्हें सामाजिक, कानूनी, नैतिक, आर्थिक और तकनीकी स्तर पर समझा जा सकता है। प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं-

डेटा गोपनीयता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में डेटा गोपनीयता एक प्रमुख चुनौती है। AI प्रणाली प्रभावी कार्य के लिए बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में उपयोगकर्ताओं की सहमति, डेटा की सुरक्षा और उसका नैतिक उपयोग सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। अपर्याप्त सुरक्षा और कमजोर सुरक्षातंत्र डेटा के दुरुपयोग तथा निजता के उल्लंघन की आशंका को बढ़ा देते हैं।

दायित्व निर्धारण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में दायित्व निर्धारण एक जटिल चुनौती के रूप में उभरता है। जब कोई AI प्रणाली त्रुटिपूर्ण निर्णय लेती है या नुकसान पहुँचाती है, तब यह स्पष्ट करना कठिन हो जाता है कि जिम्मेदारी किसकी होगी - डेवलेपर, उपयोगकर्ता या स्वयं प्रणाली की। इस अस्पष्टता के कारण न्यायिक प्रक्रिया जटिल हो जाती है और पीड़ितों को समय पर न्याय मिलना कठिन हो जाता है।

भेदभाव और पारदर्शिता

भेदभाव और पारदर्शिता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में एक गंभीर चुनौती है। AI प्रणालियाँ जिस डेटा पर प्रशिक्षित होती हैं, यदि उसमें सामाजिक पूर्वाग्रह मौजूद हो तो उनके निर्णय भी पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही अनेक AI मॉडल ‘‘ब्लैक बॉक्स‘‘ की तरह कार्य करते हैं, जिससे उनके निर्णयों की प्रक्रिया समझना कठिन हो जाता है। यह स्थिति विश्वास की कमी और सामाजिक अन्याय की आशंका को बढ़ाती है।

नैतिकता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में नैतिकता एक महत्वपूर्ण चुनौती है। AI निर्णय लेने की क्षमता रखती है, पर उसमें मानवीय संवेदना, करुणा और नैतिक विवेक का अभाव होता है। यदि इसके विकास और उपयोग में नैतिक मूल्यों को स्पष्ट रूप से शामिल न किया जाए तो यह तकनीक मानव गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए AI को मानवीय मूल्यों के अनुरूप दिशा देना आवश्यक है।

डिजिटल असमानता

यह एक गंभीर चुनौती है। AI आधारित सुविधाएँ और संसाधन अभी भी सीमित वर्गों, शहरी क्षेत्रों और तकनीकी रूप से सक्षम लोगों तक अधिक सुलभ हैं। इससे ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमजोर और कम शिक्षित वर्ग पीछे छूटने लगते हैं। यह तकनीकी प्रगति सामाजिक विषमता को कम करने के बजाय उसे और गहरा कर सकती है, यदि समावेशी नीतियां न अपनाई जाएँ।

साइबर अपराध और सुरक्षा जोखिम

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के साथ साइबर अपराध और सुरक्षा जोखिम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। AI तकनीक का उपयोग डीपफेक, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्वचालित साइबर हमलों में किया जा रहा है। इससे व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न होता है। पर्याप्त साइबर सुरक्षा ढांचा और तकनीकी जागरूकता की कमी इन जोखिमों को और गंभीर बना देती है।

नीति और विनियमन की कमी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में नीति और विनिमय (नियमन) की कमी एक बड़ी चुनौती है। तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि उसके अनुरूप कानून और दिशा-निर्देश पीछे छूट जाते हैं। स्पष्ट नियमों के अभाव में AI का दुरुपयोग, एकाधिकारवादी उल्लंघन और जवाबदेही की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए संतुलित, लचीली और भविष्य-उन्मुख नीतियों का निर्माण अत्यंत आवश्यक हो गया है।

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास की संभावनाएँ

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास भविष्य में मानव जीवन को और अधिक सरल, सुसंगत और प्रभावी बनाने की विशाल संभावनाएँ प्रस्तुत करता है। यह तकनीक केवल मशीनों की क्षमता को बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मानवीय निर्णय प्रक्रिया को सहयोग देने वाला एक संवेदनशील उपकरण बन जाएगी। आने वाले समय में AI विभिन्न क्षेत्रों में समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है।

शिक्षा के क्षेत्र में AI व्यक्तिगत सीखने को बढ़ावा देगी। उदाहरण के लिए, स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों की समझ और गति के अनुसार पाठ्य सामग्री प्रदान कर सकेंगे, जिससे कमजोर और प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल पाएंगे। शिक्षकों को मूल्यांकन और मार्गदर्शन में तकनीकी सहायता भी प्राप्त होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में AI की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। रोगों की प्रारंभिक पहचान, दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाएँ और सटीक उपचार योजनाएँ AI के माध्यम से संभव होंगी। उदाहरण के तौर पर, मेडिकल इमेजिंग में AI आधारित सिस्टम कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती पहचान में मदद कर सकते हैं।

रोजगार और अर्थव्यवस्था में AI नई संभावनाएँ उत्पन्न करेगी। हालाँकि कुछ पारंपरिक नौकरियाँ प्रभावित होंगी, लेकिन डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, AI एथिक्स और तकनीकी प्रशिक्षण जैसे नए कार्यक्षेत्र विकसित होंगे। इससे कौशल आधारित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

कृषि और ग्रामीण विकास में AI किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। फसल पूर्वानुमान, मौसम विश्लेषण और कीट नियंत्रण जैसी तकनीकों से कृषि उत्पादन अधिक व हानि के प्रति टिकाऊ हो सकेगा।

शासन और सार्वजनिक सेवाओं में AI पारदर्शिता और दक्षता बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए शिकायत निवारण प्रणाली और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन नागरिकों के जीवन को सरल बना सकते हैं।

यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास मानवीय मूल्यों, नैतिकता और समावेशिता के साथ किया जाए, तो यह भविष्य में मानव समाज के लिए सहयोगी शक्ति के रूप में उभरेगी, न कि प्रतिस्पर्धी के रूप में।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत के सामाजिक ढांचे में नए आयाम जोड़ने वाली है। यह तकनीक मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाएगी, लेकिन इसके साथ सामाजिक असमानता, बेरोजगारी और नैतिक दुविधाओं में भी वृद्धि होगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि भारत एक ऐसा नियामक ढांचा विकसित करे जो तकनीकी प्रगति और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित कर सके। AI को केवल आर्थिक उपकरण मानने के बजाय इसे सामाजिक सुधार का माध्यम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार ‘‘AI FOR ALL‘‘ का सिद्धांत तभी सार्थक होगा जब यह सभी वर्गों के विकास और समान अवसरों को सुनिश्चित करेगा।

संदर्भ

1. नीति आयोग. (2018). *राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति: AI for All.* भारत सरकार.
2. नीति आयोग. (2021). *उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता: भारत के लिए दृष्टिकोण दस्तावेज.* भारत सरकार.
3. विश्व आर्थिक मंच. (2020). *रोजगार का भविष्य रिपोर्ट.*
4. फ्लोरिडी, एल. (2019). *कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता.* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
5. रसेल, एस., और नार्विग, पी. (2021). *कृत्रिम बुद्धिमत्ता: एक आधुनिक दृष्टिकोण.* पियर्सन एजुकेशन.
6. यूनेस्को. (2019). *शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: अवसर और चुनौतियाँ.* यूनेस्को प्रकाशन.
7. शर्मा, आर., और वर्मा, एस. (2021). भारतीय शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका. *भारतीय शैक्षिक अनुसंधान पत्रिका, 15*(2), 112-124.
8. आदित्य, आनंद., और चौधरी, एस. (2020). भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव. *भारतीय सामाजिक अनुसंधान पत्रिका, 61*(2), 245-260.
9. शर्मा, आर., वर्मा, एम., और एल. (2022). सामाजिक संबंधों पर डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव. *भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका, 38*(1), 55-68.
10. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय. (2022). *भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोडमैप.* भारत सरकार.